01–: रिजनल रूरल बैंकस् एण्ड इंस्टिट्यूशनालाइजेशन ऑफ रूरल क्रेडिट– 1988– वसु सुभाष के।

02–: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की समस्याऐं– 1989 टेब्बार श्री ए.आर.के।

03–: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यवसाय का विकास– 1990– खन्ना श्री एस.एन.।

04–: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकल्प की आवश्यकता– 1992– किशोर आनंद।

05–: भारतीय ग्रामीण विकास बैंक सफलताऐं एवं संभावनाऐं– 1993– जितेन्द्र शर्मा।

06–: बिलासपुर– रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यो का आर्थिक विश्लेषण, समस्याऐं एवं संभावनाएं। 1996– देवेन्द्र कुमार वर्मा।

07–: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और आदिवासी विकास (मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले का अध्ययन्)– 2001 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव।

08–: कृषि वित्त व्यवस्था में राष्ट्रीयकृत बैंक का योगदान (जांजगीर–चांपा जिले के विशेष संदर्भ में)– 2005 श्री श्याम कुमार मधुकर।

09–: कृषि वित्त में नाबार्ड बैंक का योगदान– 2006–07– श्री मदनलाल।

10–: ग्रामीण बैंक पुर्नगठन की आवश्यकता– 1993 योजना– श्री भार्गव सुरेन्द्र कुमार।

11–: ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका–1990 योजना– जाट बी. सी.।

12–: ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान– 1992– कुरूक्षेत्र– जागिड़ धर्मपाल एवं गुप्ता।

13–: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विकास– 1991– श्री परिमन ए.के.।

प्रस्तावना–:

ऐसा अर्थशास्त्र जो ग्राम्य अर्थशास्त्र के परिवर्तनों के अध्ययन की उपेक्षा करता है आंशिक एवं अपूर्ण होता है, मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है। उस क्षेत्र की संसाधनों से उसका घनिष्ठ संबंध रहता है। मनुष्य अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं अनुभव के द्वारा इनकों विभिन्न प्रकार उपयोगों में लाता है। जहां तक ग्राप्य अर्थव्यवस्था का संबंध है, ग्रामीण इन संसाधनों को अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार उत्पादन कला से परिवर्तित कर जीविकोपार्जन का प्रबंध करते है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में वित्त का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्राम्य अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सस्ती एवं पर्याप्त साख संबंधी सुविधाओं की उपलब्धि परम आवश्यक है । ग्रामीण बिना पर्याप्त बाह्य आर्थिक सहायता के व्यवसाय, कृषि तथा अन्य उत्पादन कार्यों को पता चला पाने में असमर्थ रहते है।

भारतय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूर्णतः ग्रामीण है। यदि गांवों की काया पलट हो जाती है तो समूचे राष्ट्र का विकास संभव है, जब कृषि का उत्तरोत्तर विकास हो। ग्रामीण पूर्णरूपेण प्राथमिक उत्पादन क्रिया कलाप में लगे रहते हैं । ग्रामीणों को निम्न तीन प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है।

प्रथमः– प्रत्यक्षरूप से उत्पादन कार्यो के संचालन के लिए जैसे बीज,रसायनिक खाद, मत्सयपालन, मुर्गीपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि।

द्वितीयः– साधनों के विकास या संरक्षण के लिए जैसे भूमि, भवन,तालाब,सिंचाई, साधनों के विकास आदि।

तृतीयः– दुर्भिक्ष या बाढ़ में सहायता के लिए ऐसे वित्त की आवश्यकता साधरणतया उत्पादन तथा उपभोग संबंधी आवश्यकतों की पूर्ति के लिए होती है।

इतिहास के पन्नों को पलटें तो परिलक्षित होता है कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का ढ़ाचा काफी मजबुत था और उसका स्तर काफी ऊंचा। उस समय के अनेक यूरोपीय देशों की तुलना में यहां की आर्थिक दशा बेहतर थी। देश की खेती अच्छी थी और अनाज के संबंध में देश आत्मनिर्भर था यहां अनेक प्रकार के उद्योग जो मुख्य रूप से दस्तकारी और छोटे पैमाने के थे, निर्बाध रूप से चल रहे थे। भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था पर धीरे–धीरे राजाओं व सामन्तों के आपसी द्वेस से देश में विपरित परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इस तरह देशी राजा–महाराजाओं के शासन काल मे जमीदारी प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। वित्त पूर्ति करने के प्रमुख स्त्रोत साहूकार ही थे इन्हें ही गांव का बैंकर कहा जाता था।

ग्रामीण अपने वित्त व्यवस्था की पूर्ति प्रायः कृषि कार्यो से प्राप्त अर्थ से ही करते है। कृषि की समृद्धि जल पर निर्भर होती है पर प्राकृतिक आपदा के निराकरण हेतु ग्रामीण वित्त की पूर्ति के लिए बाह्य आर्थिक सहायत आवश्यक है। चूंकि गांव में ही बैंकर के रूप में साहुकार थे। जिनसे ऋण लेना सहज था, किन्तु इस ऋण से छुटकारा पाना कठिन हो जाता था। इन साहूकारों को देशी राजा व महाराजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इस तरह ग्रामीण इन साहूकारों से पूर्णतः शोषित थे। देश में अंग्रेजी शासन आने के बाद साहूकारों का पतन होना शुरू हो गया। ईस्ट उंडिया कंपनी की कूटनीति के कारण साहूकारों को वह संरक्षण नहीं मिल पाया जो उन्हें देशी राजा महाराजाओं से मिला करता था। ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने व्यापार व्यावसायी के विकास के लिए आधुनिक बैंकों की स्थापना करना शुरू किया।

आधुनिक अधिकोष का विकास सोलहवी शताब्दी से अंग्रेजों के भारत आगमन से प्रारंभ होता है। 1720 ई में बम्बई सरकार द्वारा एक बैंक की स्थापना की गयी। 1786 में जनरल बैंक आफ इंडिया की स्थापना की गयी थी।

किन्तु 18 वीं शताब्दी में देश में ऐसा कोई बैंक स्थापित नहीं हुआ जिसे सरकारी वित्त का कार्य सौंपा जा सके। सन् 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी की आज्ञा से बैंक आफ कलकत्ता की स्थापना हुई। इसके पश्चात 1840 में बैंक आफ बम्बई तथा 1843 में बैंक आफ मद्रास की स्थापना हुई थी। 1860 में समिति दायित्व के सिद्धांत को मान्यता मिलने के कारण भारतीय बैंकिंक व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरूआत हुई। 1881 में भारतीय प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम अर्थव्यापारीक बैंक की स्थापना हुई। 1881 में ही इलाहाबाद बैंक की तथा 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। जो आज देश के प्रसिद्ध बैंक माने जाते है।

1905 में स्वदेशी आंदोलन के शुरू होते ही देश में अनेक बैंकों की स्थापना की गयी, जैसे बैंक आफ इंडिया बैंक ऑफ बडौदा तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया आदि। 1913 से भारत में बैंकिग संकट का काल शुरू हो गया यह काल 1916–18 तक रहा। इसके पश्चात् बैंकिग स्थिति में सुधार आता गया 1923 तक बैंकों तथा इनकी शाखाओं की संख्या 560 तक पहुंच गयी थी। सन् 1946 तक भारतीय बैंकिग व्यवस्था में उत्तरोत्तर प्रगति होती चली गयी।

जब से देश स्वतंत्र हुआ है केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें देश की ग्रामीण वित्त संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करती रही है इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप 1945 में गाडगिल समिति, सन् 1950 में ग्रामीण बैंकिग जांच कमेटी सन् 1954 में ग्रामीण साख समिति की स्थापना की गई ताकि ग्रामीण वित्त के लिए सुसंगठित नियंत्रित एवं व्यवस्थित प्रणाली अपनायी जा सके। इन समितियो के सुझाओं के फलस्वरूप ही 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्घाटन किया गया। अपने विकास के विभिन्न बहुआयामी सोपानों को तय करते हुए वर्तमान में भारत में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हैं जिसमें से 24 मध्यप्रदेश में स्थापित थे, इन्हीं में से एक प्रमुख

बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित बिलासपुर–रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1979 को हुई जिसका प्रधान कार्यालय बिलासपुर में स्थित था। बिलासपुर–रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो तीनों ही भारतीय स्टेट बैंक से प्रायोजित थे, जो जून 2006 में संविलयन होकर रायपुर प्रधान कार्यालय द्वारा कार्यो का निर्वहन कर रहे है।

ग्रामीण जनता की आर्थिक सहायता के निमित अनेक साख एजेंसीयों के रहते हुए भी ग्रामीण कृषिगत वित्त की समस्या बनी रही किन्तु वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं पर दृष्टिगत करने से स्पष्ट होता है कि, आज भी ग्रामीण वित्त समस्या अपर्याप्त है एवं उनमें पर्याप्त समन्वय का अभाव हैं।

आज जहां हम आर्थिक उदारीकरण के परिवेश को अपना रहे है। ऐसी स्थिति में कृषि एवं ग्राम उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत तेजी से नहीं हो पा रहा है इसका कारण जहां एक ओर ग्रामीणों की ऋण ग्रस्तता दूसरी ओर संसाधनो के पर्याप्त होने के बाद भी वित के अभाव में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में कृशि एवं ग्रामीण वित के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों के योगदान में उदारता अत्यंत आवश्यक है। इस दिषा में ग्रामीण वित सुलभ कराने के उपक्रम मं ग्रामीण बैंक का प्रयास अनवरत जारी है ताकि ग्रामीण संसाधनों की उचित दोहान कर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा रहे है।

अनुसंधान के उत्कुश्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए सक्षम एवं समग्र अध्ययन जरूरी होता है इसीलिए सिर्फ बिलासपुर जिले को ही अपने अध्ययन का आधार बनाया है चूकि मेरा आरंभिक जीवन गांवो में व्यतीय हुआ है, अतः मैंने ग्रामीण वित को अपने अध्ययन के विषय के रूप में चयनित किया है।

शोध उद्देश्य :

1– बिलासपुर जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का महत्व।

2– छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के संसाधनों पर प्रकाश डालना।

3– बिलासपुर जिले के ग्रामीणों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन।

4– छत्तीसगढ ग्रामीण बैंक द्वारा बिलासपुर जिले के ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान का अध्ययन।

5– बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय बैंक द्वारा प्रदत्त साख एवं वित्त सुविधाओं का उपयोग एवं प्रभावोत्पादकता का अध्ययन करना।

6– छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा दी जाने वाली साख एवं वित्त सुविधा में आने वाली समस्याओं को प्रकाश में लाना एवं समापन के लिए उपाय सुझााना।

अध्ययन की सार्थकता

किसी भी देश के आर्थिक विकास में वित्त एवं साख की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। जहां तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का प्रश्न है वित्त का महत्व और अधिक बढ जाता है कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्रारंभिक राष्ट्रीय उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुनिश्चित साख एवं वित्त योजना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साख योजना '' कृषि एवं ग्रामीण वित्त पोषण'' का स्वरूप अत्यंत व्यापक होता जा रहा है कृषि विकास के समग्र पहलुओं पर ध्यान देने के साथ ही समन्वित ग्रामीण विकास और लधु एवं कुटीर उद्योग के कृषियेत्तर हिस्से के वित्त पोषण को ग्रामीण वित्त पोषण के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया गया है इसका उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ–साथ ग्रामीण साधनों में वृद्धि के द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति अवरूद्ध आय में बढ़ोत्तरी लाना है। इसीलिए क्षेत्रीय स्तर पर विकासात्मक कार्य में संबद्ध सभी संस्थाओं के ग्रामीण साख कार्यकलापों में समन्वय हेतु विशेष कार्यक्रम बनाने ऋण वितरण प्रणाली को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप करने तथा इस कार्य में संलग्न वित्तीय संस्थाओं की कार्यक्षमता में सुधार लाने की विशेष आवश्यकता समय की मांग है।

'' आज बैंकर'' कृषि एवं ग्रामीण वित्त पोषण को महत्वपूर्ण दायित्व के रूप में देखता है तथा ग्रामीण किसान समुदाय के जीवन में अपनी बढ़ती हुई सहभागिता की आवश्यकता निरंतर महसूस करता है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकाधिक सुविधाये प्रदान करने कृषी एवं कृषियेत्तर कार्यकलापों में समन्वय के द्वारा आर्थिक ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा निजी कृषक एवं उनके परिवारों के अधिकाधिक कल्याण करने एवं उनसे संबंध स्थापित करने पर विशेष बल दिया है, जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऋण संस्थाओं के संसाधनों में वृद्धि, विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सुनिश्चित करने एवं ऋण वितरण प्रणाली को सरल एवं न्यायपूर्ण बनाये जाने पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसी कडी में कृषि एंव ग्रामीण वित्त एवं साख व्यवस्था सहभागी संस्थाओं में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अविकसित एवं पिछड़ी हुई अवस्था का प्रमुख कारण वित्तीय सुविधाओं का अभाव है, जो कि पूर्णतया कृषि एवं सहसंबंधित उद्योगों पर अवलंबित है, जिनसे ही ग्रामीण अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने है। छत्तीसगढ़ जो ''धान का कटोरा'' कहलाता है, बिलासपुर जिला उसी का एक हिस्सा है, किन्तु प्राकृतिक असंतुलन एवं पिछड़ी कृषि प्रणाली के कारण कृषि आय बहुत ही कम होती है, जिससे बचत एवं विनियोग की आशा बेमानी ही है।

शोध प्रविधि :

शोध के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता प्रचलित शोध विधि एवं अन्य उपलब्ध विधियों का अनुकूलतम आधार पर चयन कर अध्ययन करता है प्रस्तुत शोध समस्या के निरूपण हेतु बिलासपुर जिले के समग्र रूप में चयन किया गया है, तथा ग्रामीण वित्त व्यवस्था में छत्तीसगढ ग्रामीण बैंक के योगदान का मुल्यांकन करने के लिए बिलासपुर जिले को प्रशासनिक तहसीलों ने विभाजित कर तहसीलों के अंतर्गत स्थित बैंक शाखाओं को आधार मानकर अध्ययन किया जावेगा।

उपरोक्त संदर्भ में बैंक शाखाओं द्वारा प्रदत्त लाभाविन्त ऋण सूचियों में से दैव निर्देशन पद्धति द्वारा लाभान्वित ऋणियों का चयन कर प्राथमिक समंकों का एकत्रिकरण, साक्षात्कार, अवलोकन प्रश्नावली एवं अनुसूचि के माध्यम से किया जाना है।

प्रस्तावित शोध प्रबंध के अंतर्गत द्वितीयक समंक संग्रहण हेतु प्रकाशित, अप्रकाशित व्यक्तिगत एवं संस्थागत सामाग्री का प्रयोग किया जाना है। इसमें बैंक प्रतिवेदन, गजेटयर्स, जर्नलस, वित्तीय स्थिति विवरण, लिड बैंक एक्शन प्लान आदि का प्रयोग किया जाना है, साथ ही विषय से संबंधित विद्वानों से प्राप्त परामर्श एवं सूझावों का भी सहारा लिया जाना है, जो शोध के स्तर को विषय अनुरूप बनाये रखने के लिए उपयुक्त होगा।

उपरोक्त वर्णित उद्देश्य एवं अध्ययन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संकलित की गयी समंकों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं सांख्यिकी विशलेषण स्वयं के प्रयास द्वारा व आवश्यकतानुसार संगणक की सहायता से किया जावेगा, जिसमें सांख्यिकीय तथा लेखाकर्म विधियों का समाविष्ट किया जावेगा, ताकि प्रस्तावित शोध कार्य पूरा किया जा सके।

शोध सीमा :

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के बिलासपुर जिले के वित्तीय वर्ष 2005–2010 तक की कार्यविधि का अवलोकन कर यथेष्ट निश्कर्ष पर पहुंचा जावेगा। यद्यपि छत्तीसगढ ग्रामीण बैंक के कार्य क्षेत्र में बिलासुपर, रायपुर, रायगढ़ एवं दुर्ग जिलों का सामावेश होता है, परन्तु उतकृष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म अध्ययन नितांत जरूरी होता है।

अतः इस अध्ययन में सिर्फ बिलासपुर जिले को ही अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लिया गया है।

परिकल्पनाएं :

प्राकल्पना शब्द का तात्पर्य पूर्व चिन्तन है यह अनुसंधान तथा सर्वेक्षण प्रक्रिया का आधारभूत चरण है। प्राकल्पना एक विचार दशा तथा प्रस्ताव है जिसे संभवतः अस्थायी रूप से मान लिया जाता है, ताकि तार्किक परिणाम निकाले जा सके, तथा जिसे ज्ञात अथवा निर्धारित किये जाने वाले तथ्यों की सहायता से विचार की सत्यता की जांच की जा सके।

प्रस्तुत शोध की पूर्ति हेतु परिकल्पनाएं निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है–

1 ग्रामीण वित्त व्यवस्था में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

2 ग्रामीणों की आर्थिक विकास में बैंक का सर्वोच्च योगदान है।

3 गैर उत्पादक कार्यो के लिए साख सुविधा प्रदान की जा रही है।

4 ऋण की वापसी एवं वसूली नियमित रूप से हो रही है।

5 छत्तीसगढ ग्रामीण बैंक, ग्रामीण अंचलों में बसे हुए समाजिक, आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के लोगों को ही साख उपलब्ध कराता है।

6 छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक ग्रामीण बचतों को आकर्षित एवं संग्रह करने में सफल रहा है।

अनुक्रमणिका

सम्पूर्ण अध्ययन निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित रहेगा,

अध्याय–1 1. प्रस्तावना

2. अध्ययन उद्‌देश्य

3. अध्ययन परिकल्पना

4. अध्ययन प्रविधि

5. अध्ययन क्षेत्र एवं सीमा

अध्याय–2

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना उद्‌देश्य एवं राज्य की पृष्ठभूमि

(ब) बिलासपपुर जिले का अध्ययन

1. बिलासपुर जिले की पृष्ठभूमि
2. बिलासपुर जिले की भौगोलिक स्थिति
3. बिलासपुर जिले की जनांकीय स्थिति
4. बिलासपुर जिले में उपलब्ध भूमि उपयोग एवं कृषिगत स्थिति
5. बिलासपुरजिले में पशुधन
6. बिलासपुर जिले में वन संसाधन
7. बिलासपुर जिले में बैंकिग सुविधा
8. बिलासपुर जिले में लघु एवं कुटीर उद्योग

अध्याय–3

ग्रामीण वित्त व्यवस्था एक सैद्धांतिक विवेचन

1. ग्रामीण वित्त से आशय
2. ग्रामीण वित्त की आवश्यकता

3. ग्रामीण वित्त व्यवस्था की स्त्रोत

अ– संस्थागत वित्त व्यवस्था

1. व्यापारिक बैंक

2. भूमि विकास बैंक

3. सहकारी समिति

4. ग्रामीण बैंक

ब– गैर संस्थागत वित्त व्यवस्था

1. महाजन

2. देशी बैकर

अध्याय–4

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक स्थापना एवं संगठन

1. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की आवश्यकता

2. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की स्थापना एवं उद्देश्य

3. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का संगठन एवं प्रबंध

4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के कार्य क्षेत्र बिलासपुर जिले के संदर्भ में

5. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त विभिन्न ऋणों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

अध्याय–5

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के संसाधन एवं विनियोजन

अ. संसाधन

1. अंश पूंजी

2. जमा योजना

3. पुनर्वित (नाबार्ड द्वारा)

4. डी.आई.सी.जी.सी.

5. अन्य प्राप्तियां

1– ब्याज

2– कमीशन

ब. विनियोजन

1– ऋण

2– वैधानिक कोषानुपात

3– नगद कोषानुपात

4– अन्य विनियोगों की स्थिति

अध्याय–6

बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व्यवस्था

1. कृषकों को ऋण

1– उच्च कृषक 10 एकड़ से अधिक

2– मध्य या 5–10 एकड़ तक

3– सीमांत या लघु कृषक 5 एकड़ से कम

2. पशुपालन हेतु प्रदत्त ऋण

3. व्यवसाय हेतु प्रदत्त ऋण

4. कारीगरो को प्रदत्त ऋण

1. परम्परागत धंधा कार्य से जुड़े हुए
2. गैर परम्परागत कार्य से जुड़े हुए
3. व्यवसाय हेत प्रदत्त ऋण

अध्याय–7

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की वापसी व ऋण शेष का अध्ययन बिलासपुर जिले के संदर्भ में

अध्याय–8

अ– छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का ग्रामीण वित्त व्यवस्था में योगदान का मूल्यांकन

ब– प्रदत्त ऋण की प्रभावोत्पादकता

1– आय पर प्रभाव

2– सम्पत्ति निर्माण पर प्रभाव

3– बचत पर प्रभाव

4– सामाजिक स्थिति पर प्रभाव

अध्याय–9

निष्कर्ष, समस्याएँ, अनुशंसाएं एवं उपसंहार

संदर्भ ग्रंथ

1. ग्रामीण बस्ती भूगोल – जी.पी.यादव
2. विकासमान बैंकिंग एवं ग्रामीण विकास – श्याम लाल गौण
3. भारतीय अर्थव्यवस्था – मिश्र एवं पुरी
4. कृषि एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र – पी.सी.मिश्रा
5. ग्रामीण अर्थशास्त्र – पी. मिश्रा
6. मुद्रा, बैंकिंग, एवं राजस्व – डॉ. हिरणचन्द्र शर्मा
7. भारत का अधिक विकास – चैनसिंह बरला एवं आर.सी.अग्रवाल
8. भारतीय कृषि का अर्थशास्त्र – एन. एल. अग्रवाल
9. भारतीय बैंकिंग प्रणाली – डी.एन.माथुर एवं पी.सी.जैन
10. भारत के कृषि विकास – पी.सी.जैन
11. भारतीय आर्थिक समस्याएं एवं अंतराष्ट्रीय व्यापार – प्रो. पी.सी.मिश्रा
12. उच्च मौद्रिक अर्थशास्त्र – एस.पी.मित्तल
13. वाणिज्यिक भूगोल – डॉ. मामोरिया
14. भारतीय अर्थव्यवस्था – भारती एंव पाण्डेय
15. योजना पत्रिकाएं
16. कुरूक्षेत्र पत्रिकाएं

शोध निर्देशक	अध्यक्ष	शोध छात्र
डॉ. राजेन्द्र कुमार शुक्ल	डी.आर.सी.	खगेन्द्र कुमार सोनी
सहा. प्राध्यापक वाणिज्य	डॉ. एस.एस.खनुजा	एम.कॉम.एम.फिल
दुर्गा महाविद्यालय	दुर्गा महाविद्यालय	
रायपुर (छ.ग.)	रायपुर (छ.ग.)	